केन्द्रीय विद्यालयों में उर्दू के अध्यापक

3262. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में किसी भी केन्द्रीय विद्यालय में उर्दू के अध्यापक नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन विद्यालयों में उर्दू अध्यापकों की नियुक्ति करने का विचार रखती है और यदि हां, तो इस संबंध में अब तक की गयी पहल का ब्यौरा क्या है और कितने विद्यालयों में उर्दू के अध्यापक नियुक्त कर दिये गये हैं; और

(ग) शेष केन्द्रीय विद्यालयों में उर्दू के अध्यापकों की कब तक नियुक्ति कर दिये जाने की संभावना है और इस संबंध में विलंब के क्या कारण है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री एल० पी० साहो) : (क) से (ग) उर्दू को पहले पढ़ाने की व्यवस्था उन केन्द्रीय विद्यालयों में भी जारी थी जहां 20 अथवा इससे अधिक छात्रों ने इसके लिए विकल्प दिया और इसका अध्यापन उन अन्य विषय के विद्यमान शिक्षकों द्वारा कराया गया था जिन्हें भाषा में दक्षता प्राप्त है।

अब केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने यह तय किया है कि हरियाणा के 6 केन्द्रीय विद्यालयों में, उत्तर प्रदेश के 10 केन्द्रीय विद्यालयों में, मध्य प्रदेश के 4 केन्द्रीय विद्यालयों में तथा जम्मू और काश्मीर के काश्मीर और लद्धाख क्षेत्रों के सभी केन्द्रीय विद्यालयों में उर्दू भाषा त्रिभाषा सूत्र के अन्तर्गत तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जानी चाहिए। विद्यालयों में दिसम्बर, 1988 के अन्त तक उर्दू के अध्यापन के प्रबन्ध कर दिए जाने की आशा की जाती है। अध्यापन या तो सम्बन्धित केन्द्रीय विद्यालय के चुने विद्यमान शिक्षको द्वारा कराया जाएगा जिन्हें भाषा में दक्षता प्राप्त हो अथवा मासिक समेकित वेतन के आधार पर इस प्रयोजनार्थ नियुक्त अंशकालिक शिक्षकों द्वारा कराया जाएगा। यदि भाषा को जानने वाले केन्द्रीय विद्यालय के नियमित शिक्षक उपलब्ध न हों।

पत्तनों पर सामान उतारने चढ़ाने वाले उपकरणों का आधुनिकीकरण

3263. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के सभी पत्तनो पर माल उतारने और चढ़ाने वाले उपकरण पुराने पड़ गये है;

(ख) यदि हां, तो इन सभी पत्तनों पर इनका आधुनिकीकरण किये जाने तथा नए उपकरणों की अधिष्ठापना के लिए जनवरी 1988 से अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है और किन-किन पत्तनों का आधुनिकीकरण किया गया है; और

(ग) किन किन पत्तनों का आधुनिकीकरण किया जाना शेष है तथा इस संबंध में प्रस्तावित योजना का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) जी नहीं

(ख) और (ग) पत्तनो का आधुनिकीकरण एक सतत प्रक्रिया है जिसमें उपकरणो को बदलना तथा अतिरिक्त सुविधाओं का प्रावधान करना शामिल है और सातवीं योजना में सभी 10 महापत्तनों के आधुनिकीकरण तथा एक नए महापत्तन के निर्माण का प्रावधान है। विभिन्न पत्तनो में जनवरी, 1988 से स्वीकृति क्षमता में बढ़ोतरी सहित

महत्वपूर्ण बड़ी स्कीमें नीचे दी गई हैं :–

स्कीम का नाम	संस्वीकृत लागत (करोड़ रु०)
1. कोचीन पोर्ट में कंटेनर बर्थ	53.11
2. मद्रास पोर्ट में भारती गोदी में कंटेनर टर्मिनल का विस्तार	54.71
3. मुरगांव पत्तन में अतिरिक्त कार्गो बर्थ और 1250 टी०पी०एच० क्षमता के अनलोडर की स्थापना	7.98

सातवीं पंचवर्षीय योजना में भारत में महापत्तनों के आधुनिकीकरण और विकास के लिए लगभग 955 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।

Train service between Delhi and Kannauj

3264. SHRI ANAND PRAKASH GAUTAM: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is no direct train service for Delhi from Kannauj in Uttar Pradesh; and

(b) if so, what steps are being taken by Government in this regard?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MAHABIR PRASAD): (a) and (b) Yes, Sir. The all metre gauge route is too circuitous. Fast connected service is available on B.G. cum M.G. via Farrukhabad.

Declaring Delhi-Kanpur Road as National Highway

3265. SHRI ANAND PRAKASH GAUTAM: Will the Minister of SURFACE TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether the Uttar Pradesh Government has urged the Central Government to convert the road between Kanpur and Delhi into a National Highway; and

(b) if so, what action has been taken by Government thereon?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT (SHRI RAJESH PILOT): (a) Yes, Sir.

(b) Owing to resources constraint and other priority considerations it is not possible at present to declare this road as National Highway. However Kanpur is linked with Delhi by National Highway No. 2.

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में अनसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की संख्या के प्रतिशत का कम होना

3266. **श्री अजीत जोगी :** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री 11 नवम्बर, 1987 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 396 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में बी० टैक० पाठयक्रम में प्रवेश पाने वाले अनसूचित जातियों तथा आदिवासी छात्रों के बहुत कम प्रतिशत को ध्यान में रखते हुए, इन छात्रों के लिए स्थानों की संख्या में वृद्धि करने के लिए कोई कदम उठा रही है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और